



दो राज्यों, दो रणनीतियां: केरल में कल्याण का कार्ड असम में सख्ती का संदेश—भाजपा का घोषणापत्र जारी

तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी से आई खबरों ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरने का मन बना लिया है। मंगलवार, 31 मार्च 2026 को पार्टी ने केरल और असम—दोनों राज्यों के लिए अपने-अपने घोषणापत्र जारी किए, जिनमें क्षेत्रीय जरूरतों और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग-अलग प्राथमिकताएं तय की गई हैं। एक ओर केरल में कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक सहायता का बड़ा पैकेज पेश किया गया है, वहीं असम में सुरक्षा, पहचान और भूमि से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखा गया है। केरल में भाजपा नीत राज ने अपने

घोषणापत्र के जरिए सीधे तौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और गरीब तबके को साधने की कोशिश की है। पार्टी ने वादा किया है कि जरूरतमंद महिलाओं और 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही गरीब परिवारों को साल में दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का एलान भी किया गया है, जो सीधे तौर पर घरेलू खर्च को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा, सीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए 'भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड' की योजना पेश की गई है, जिसके तहत हर महीने 2,500 रुपये का रिचार्ज मिलेगा, जिसे दवाइयों और रोजमर्रा के सामान पर



खर्च किया जा सकेगा। घोषणापत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी खास जगह दी गई है। पार्टी ने देवस्वामि बोर्ड के पुनर्गठन का वादा किया है, जिससे सबरीमाला और गुरुवापुर जैसे प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन में पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। साथ

ही, सबरीमाला सोना चोरी मामले में समयबद्ध सीबीआई जांच कराने की बात कहकर भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया है। इस दौरान भाजपा नेतृत्व ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की जनता लंबे समय से पारंपरिक राजनीतिक दलों के बीच फंसी हुई है और अब बदलाव चाहती है। वहीं दूसरी ओर असम में भाजपा का घोषणापत्र एक अलग ही राजनीतिक स्वर प्रस्तुत करता है, जिसमें पहचान, सुरक्षा और भूमि अधिकार जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। Himanta Biswa Sarma के नेतृत्व में पार्टी ने 'लव जिहाद' और 'लैंग जिहाद' जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने का वादा किया है। इसके साथ ही

बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई जमीन को वापस लेने और 'मिशन वसुंधरा' के तहत वास्तविक नागरिकों को भूमि अधिकार देने की बात कही गई है। यह साफ संकेत है कि पार्टी असम में अपनी पहचान-आधारित राजनीति को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का भी वादा किया गया है, जिसे सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर लागू करने की बात कही गई है। Himanta Biswa Sarma ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कानून को लागू करते समय जनजातीय समुदायों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा

युवाओं को साधने के लिए दो लाख सरकारी नौकरियां देने और 'मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान' के जरिए उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना पेश की गई है। आर्थिक विकास को लेकर भी भाजपा ने बड़े लक्ष्य तय किए हैं। 'असम गति शक्ति मास्टर प्लान' के तहत 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का रोडमैप पेश किया गया है, जिससे राज्य को एक आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, बाढ़ जैसी पुरानी और गंभीर समस्या से निपटने के लिए 18,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'बाढ़ मुक्त असम मिशन' शुरू करने का संकल्प लिया गया है। यह योजना सीधे तौर पर राज्य

के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जो हर साल बाढ़ की मार झेलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा ने दोनों राज्यों में पूरी तरह अलग रणनीति अपनाई है। केरल में जहां सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के जरिए वोटों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, वहीं असम में पहचान, सुरक्षा और विकास के मिश्रण के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। अब देखना यह होगा कि इन वादों का असर जमीनी स्तर पर कितना पड़ता है और क्या भाजपा इन दोनों राज्यों में अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल कर पाती है या नहीं।

अमरावती को मिलेगा कानूनी दर्जा: वर्षों का विवाद खत्म होने की ओर, नई राजधानी का सपना आकार लेता हुआ

आंध्र प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक दिशा तय करने वाला एक बड़ा फैसला अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। वर्षों से जारी बहस, विरोध, आंदोलन और कानूनी प्रयत्नों के बाद अब अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी बनाने की प्रक्रिया कानून के जरिए पूरी की जा रही है। केंद्र की एनडीए सरकार 1 अप्रैल 2026 को लोकसभा में 'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश करने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य अमरावती को आधिकारिक और कानूनी रूप से राज्य की स्थायी राजधानी घोषित करना है। इस कदम केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि एक लंबे राजनीतिक संघर्ष का परिणाम है। जब वर्ष 2014 में Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 के तहत आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और Telangana का गठन हुआ, तब हैदराबाद को दोनों राज्यों की साझा राजधानी के रूप में अधिकतम 10 वर्षों के लिए रखा गया था। इस दौरान आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी विकसित करनी थी। हालांकि, उस कानून में अमरावती का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं था, जिससे आगे चलकर राजनीतिक विवादों और असमंजस की स्थिति बनी रही। इसी कानूनी कमी को दूर करने के लिए



अब संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह प्रावधान जोड़ा जाएगा कि अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी। इस एक लाइन के जुड़ने से वर्षों से चल रही कानूनी अस्पष्टता समाप्त हो जाएगी और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को स्थायित्व मिलेगा। इस फैसले की नींव राज्य स्तर पर पहले ही रखी जा चुकी है। 28 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से अमरावती को एकमात्र राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu ने स्वयं सदन में प्रस्तुत किया

था। इसके बाद इसे केंद्र सरकार और संसद के संबंधित अधिकारियों को भेजा गया, जिससे अब यह प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अब कोई भी ताकत अमरावती को राजधानी बनने से नहीं रोक सकती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अमरावती को केवल एक प्रशासनिक केंद्र ही नहीं, बल्कि एक विश्वस्तरीय 'ब्लू-ग्रोन सिटी' के रूप में विकसित करना चाहती है—जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पर्यावरणीय संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

अमरावती की परिकल्पना केवल सरकारी भवनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित, स्मार्ट और टिकाऊ शहर के रूप में विकसित करने की योजना का हिस्सा है। इसमें चौड़ी सड़कें, आधुनिक परिवहन प्रणाली, हरित क्षेत्र, नदी के किनारे विकसित शहरी ढांचा और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने वाले व्यावसायिक केंद्र शामिल हैं। कृष्णा नदी के किनारे स्थित यह शहर भविष्य में दक्षिण भारत का एक बड़ा आर्थिक और प्रशासनिक हब बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। लंबे समय तक राजधानी को लेकर राज्यों में अलग-अलग प्रस्ताव सामने आते रहे—कभी तीन राजधानियों का विचार, तो कभी विकेंद्रीकरण की बात। लेकिन अब केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर स्पष्ट सहमति के साथ अमरावती को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। अपने वाले दिनों में जब यह विधेयक संसद से पारित होगा, तो न केवल आंध्र प्रदेश को एक स्थायी प्रशासनिक पहचान मिलेगी, बल्कि यह फैसला राज्य के भविष्य की ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करना सपना, जो कभी एक योजना मात्र था, अब धीरे-धीरे एक साकार होती वास्तविकता बनता दिखाई दे रहा है।

बंगाल की सियासत में 'वोटर लिस्ट' बना बड़ा मुद्दा—ममता बनर्जी ने उठाए गंभीर सवाल

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां चुनाव केवल सत्ता को लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर बहस का केंद्र बन चुका है। विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री Mamata Banerjee द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा गया पत्र अब एक बड़े राजनीतिक और संवैधानिक विमर्श का विषय बन गया है। इस पत्र में लगाए गए आरोप केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि उस विश्वास पर सवाल हैं, जिस पर पूरा लोकतांत्रिक ढांचा टिका होता है—मतदाता सूची की शुद्धता और निष्पक्षता। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में जिस तरह 'फर्जी वोटों' के मुद्दे को उठाया है, वह सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को चुनौती देता है। उनका कहना है कि राज्य में संगठित तरीके से बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि Bharatiya Janata Party से जुड़े लोग हजारों की संख्या में फॉर्म-6 जमा कर रहे हैं, जो एम मतदाताओं के पंजीकरण के लिए उपयोग होता है। इस प्रक्रिया के जरिए कथित रूप से ऐसे लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिनका राज्य से कोई भी संबंध नहीं है। यदि यह आरोप सही साबित होता है, तो यह केवल एक



राज्य का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश की चुनावी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर सकता है। मुख्यमंत्री ने इस पूरी प्रक्रिया को 'वोटर हाइजैकिंग' की संज्ञा दी है। यह शब्द अपने आप में बताता है कि वे इसे कितनी गंभीर साजिश मान रही हैं। उनका कहना है कि इस तरह की रणनीति पहले भी कुछ राज्यों में अपनाई जा चुकी है, जिससे चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सके। हालांकि इन दावों की पुष्टि या खंडन चुनाव आयोग और अन्य जांच एजेंसियों के स्तर पर ही संभव है, लेकिन इस तरह के आरोप चुनावी माहौल को बेदर संवेदनशील बना देते हैं। इस पूरे विवाद का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पहलू है चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर उठे सवाल। Election Commission of India की SIR

(Special Intensive Revision) प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाना होता है, अब विवाद के केंद्र में आ गई है। ममता बनर्जी का आरोप है कि इस प्रक्रिया में संतुलन की कमी है। एक तरफ लाखों वास्तविक मतदाता सत्यापन के नाम पर अटक हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कथित रूप से फर्जी आवेदन तेजी से स्वीकार किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 60 लाख वास्तविक मतदाता अभी भी इस जांच प्रक्रिया में फंसे हुए हैं, जिससे उनके मतदान के अधिकार पर सीधा असर पड़ सकता है। यह स्थिति केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक चिंता का विषय भी बन गई है। जब एक आम नागरिक को यह महसूस होने लगता है कि उसका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित नहीं है, या उसका वोट के स्तर पर ही संभव है, लेकिन इस तरह के आरोप चुनावी माहौल को बेदर संवेदनशील बना देते हैं। इस पूरे विवाद का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पहलू है चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर उठे सवाल। Election Commission of India की SIR

सबसे गंभीर दावा जो मुख्यमंत्री ने किया, वह इस प्रक्रिया के दौरान हुई मौतों को लेकर है। उन्होंने कहा कि अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा यदि सही है, तो यह केवल चुनावी प्रक्रिया को खामी नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी का संकेत है। हालांकि इन मौतों के कारणों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह मुद्दा अब केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों के जीवन और सुरक्षा से भी जुड़ गया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह मुद्दा आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तृणमूल कांग्रेस इसे लोकतंत्र की रक्षा और बंगाल की अस्थिरता से जोड़कर प्रस्तुत कर रही है, जबकि विपक्ष इन आरोपों को निराधार बताते हुए परतंत्र कर सकता है। ऐसे में पूरा चुनावी विमर्श विकास, रोजगार और बुनियादी मुद्दों से हटकर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर केंद्रित होता जा रहा है। आगे की राह काफी हद तक Election Commission of India के कदमों पर निर्भर करेगी। यदि आयोग इस मामले में पारदर्शी जांच करता है और सभी पक्षों को संतुष्ट करने वाला समाधान निकालता है, तो चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बना रह सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के साणंद में Kaynes Semicon प्लांट का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के साणंद में Kaynes Technology के सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया। इसके साथ ही इस केंद्र में उत्पादन कार्य शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे 28 फरवरी को Micron प्लांट में उत्पादन शुरू होने के अवसर पर साणंद में मौजूद थे, और ठीक एक महीने बाद Kaynes की इस उपलब्धि के अवसर पर फिर से यहाँ आए हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा की गति की जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा, "यह महत्त्वपूर्ण संयोग नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कितनी तेजी से विकसित हो रहा है।" प्रधानमंत्री ने Kaynes Technology के नेतृत्व, गुजरात सरकार और प्लांट में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि एक भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर लिपि निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा है। उन्होंने बताया कि Kaynes अब वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन गई है। श्री मोदी ने कहा, "यह एक शानदार शुरुआत है। आने वाले दिनों में, कई भारतीय कंपनियों वैश्विक सहयोग के माध्यम से दुनिया को मजबूत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करेंगी।" प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की यह उपलब्धि वास्तव में 'Make in India, Make for the World' (भारत में बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ) के मंत्र को साकार करती है। यह प्लांट कैलिफोर्निया स्थित एक कंपनी को 'इंटीलिजेंट पावर मॉड्यूल्स' की आपूर्ति कर रहा है और इसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा पहले ही निर्यात के लिए एक हो चुका है। उन्होंने कहा कि साणंद और सिलिकॉन वैली के बीच असल में एक नया पुल बन गया है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "साणंद में बने ये मॉड्यूल्स अमीरी की कंपनियों तक पहुँचेंगे और वहीं से पूरी दुनिया को ऊर्जा प्रदान करेंगे।" प्रधानमंत्री ने इस फेक्टरी में बन रहे इंटीलिजेंट पावर मॉड्यूल्स के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये भारत और दुनिया, दोनों



के विकास की भी जानकारी दी जो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक ऑटोमेशन के लिए सुरक्षित प्रोसेसर प्लेटफॉर्मों को मुहैया कराता है। श्री मोदी ने कहा, "भारत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के हर स्तर पर डिजाइन और निर्माण की क्षमता विकसित कर रहा है।" प्रधानमंत्री ने भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा के अगले चरण की घोषणा करते हुए, 'इंडिया-सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' के बारे में बात की, जिसे इस वर्ष के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। सेमीकंडक्टर उपकरणों और सामग्रियों के घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस नए चरण का लक्ष्य पूर्ण-स्तरीय भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "हमारा प्रयास अब ऐसा इकोसिस्टम बनाना है, जिससे हम घरेलू और वैश्विक, दोनों तरह की सप्लाई चेन में बड़ी साझेदारियाँ कर सकें।" प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए तैयार श्रमशक्ति बनाने के भारत के प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने बताया कि 85,000 से ज्यादा डिजाइन पेशेवरों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य बहुत जल्द हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने 'विस्प टू स्टार्टअप' कार्यक्रम के बारे में भी बात की, जिसके तहत लगभग 400 विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप को आधुनिक डिजाइन टूल्स तक पहुँच दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 55 से ज्यादा चिप्स का डिजाइन और निर्माण हुआ है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "तकनीकी विकास और कुशल श्रमशक्ति को साथ-साथ चलना चाहिए, और भारत इन दोनों को सुनिश्चित कर रहा है।" प्रधानमंत्री ने उद्योग के अनुमानों का हवाला देते हुए बताया कि भारत का सेमीकंडक्टर बाजार अभी लगभग \$50 बिलियन का है और इस दशक के अंत तक इसके \$100 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। भारत के सेमीकंडक्टर संकलन के बारे में वैश्विक निवेशकों में दिख रहे जबरदस्त उत्साह को

देखते हुए, श्री मोदी ने कहा, "हमारा लक्ष्य अपनी जरूरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स यहाँ भारत में बनाना है।" प्रधानमंत्री ने भारत के समानांतर प्रयासों के बारे में बात की, जिनका उद्देश्य कच्चे माल की मजबूत सप्लाई चेन सुनिश्चित करना है। इन प्रयासों में 'पैक्स सिलिका' (Pax Silica) में भारत की सदस्यता और 'राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनेरल्स मिशन' की शुरुआत शामिल है। उन्होंने खनिज रीसाइक्लिंग के लिए 1,500 करोड़ रुपये की योजना और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे तटीय राज्यों में पेश किया गया था। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में पेशेवरों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य बहुत जल्द हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने 'विस्प टू स्टार्टअप' कार्यक्रम के बारे में भी बात की, जिसके तहत लगभग 400 विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप को आधुनिक डिजाइन टूल्स तक पहुँच दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 55 से ज्यादा चिप्स का डिजाइन और निर्माण हुआ है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "तकनीकी विकास और कुशल श्रमशक्ति को साथ-साथ चलना चाहिए, और भारत इन दोनों को सुनिश्चित कर रहा है।" प्रधानमंत्री ने उद्योग के अनुमानों का हवाला देते हुए बताया कि भारत का सेमीकंडक्टर बाजार अभी लगभग \$50 बिलियन का है और इस दशक के अंत तक इसके \$100 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। भारत के सेमीकंडक्टर संकलन के बारे में वैश्विक निवेशकों में दिख रहे जबरदस्त उत्साह को

देखते हुए, श्री मोदी ने कहा, "हमारा लक्ष्य अपनी जरूरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स यहाँ भारत में बनाना है।" प्रधानमंत्री ने भारत के समानांतर प्रयासों के बारे में बात की, जिनका उद्देश्य कच्चे माल की मजबूत सप्लाई चेन सुनिश्चित करना है। इन प्रयासों में 'पैक्स सिलिका' (Pax Silica) में भारत की सदस्यता और 'राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनेरल्स मिशन' की शुरुआत शामिल है। उन्होंने खनिज रीसाइक्लिंग के लिए 1,500 करोड़ रुपये की योजना और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे तटीय राज्यों में पेश किया गया था। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में पेशेवरों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य बहुत जल्द हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने 'विस्प टू स्टार्टअप' कार्यक्रम के बारे में भी बात की, जिसके तहत लगभग 400 विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप को आधुनिक डिजाइन टूल्स तक पहुँच दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 55 से ज्यादा चिप्स का डिजाइन और निर्माण हुआ है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "तकनीकी विकास और कुशल श्रमशक्ति को साथ-साथ चलना चाहिए, और भारत इन दोनों को सुनिश्चित कर रहा है।" प्रधानमंत्री ने उद्योग के अनुमानों का हवाला देते हुए बताया कि भारत का सेमीकंडक्टर बाजार अभी लगभग \$50 बिलियन का है और इस दशक के अंत तक इसके \$100 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। भारत के सेमीकंडक्टर संकलन के बारे में वैश्विक निवेशकों में दिख रहे जबरदस्त उत्साह को

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

संपादकीय

बेकद्री पर कटेगा वेतन

वैसे तो यह किसी भी सम्य समाज के लिये शर्मनाक है कि जन्म देकर पालन-पोषण करने वाले मां-बाप की जीवन की सांझ में बेकद्री की जाए। फिर गुजारे भत्ते के लिये कानून-प्रशासन से मांग करनी पड़े। लेकिन यह मौजूदा समय की हकीकत है कि ऐसे क्रिस्से गाहे-बगाहे सुनने को मिलते हैं। सही मायनों में बुढ़ापा अपने आप में बड़ी चुनौती है, जब शरीर की क्षमताओं का ह्रास होने लगता है और आय के स्रोत लगभग खत्म होने लगते हैं। सेवानिवृत्ति की जमा-पूंजी बच्चों की पढ़ाई, शादी-ब्याह और मकान बनाने में खर्च हो जाती है। उन लोगों की स्थिति तो और दुःखद हो जाती है जो निजी क्षेत्र या किसी प्राइवेट काम-धंधे में लगे रहते हैं। उन्हें तो पेंशन भी नहीं मिलती। वहीं धीरे-धीरे अक्षम होता शरीर उध्दराज होने पर लगने वाली बीमारियों का घर बन जाता है। ऐसे स्थिति में अपने जब मां-बाप की देखभाल न करे तो यह एक सामाजिक अपराध ही कहा जाएगा। जाहिर है, जब खून के रिस्ते साथ न दें तो कानून ही अंतिम सहाय रह जाता है। इस दिशा में तेलंगाना विधानसभा में पारित तेलंगाना कर्मचारी जवाबदेही और माता-पिता सहायता निगरानी विधेयक 2026 पूरे देश के बुजुर्गों के लिये एक नई उम्मीद जगाता है। इस राज्य की विधानसभा ने बीते रविवार वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विधेयक पारित किया। निस्संदेह, देश में पहले से एक राष्ट्रीय कानून 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007' मौजूद है, लेकिन नये विधेयक का दायरा विस्तृत है। जो पहले कानून की कुछ विसंगतियों को दूर करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के नये विधेयक के दायरे में जनप्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। यह विधेयक जन प्रतिनिधियों, सरकारी व निजी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना सुनिश्चित करता है।

तेलंगाना विधानसभा में पारित यह विधेयक करनी बनाता है कि यदि दूचके मां-बाप की देखभाल नहीं करते तो उनके वेतन से पंद्रह फीसदी या दस हजार रुपये, जो भी कम है, शिकायत मिलने पर माता-पिता को देना राशि के रूप में काटे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि अपनी चले-अचल संपत्ति बेटे के नाम करने वाले महाशूर कारोबारी विजयपत सिंघानिया की बेदखली का एक मामला चर्चा में आया था। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा और देश में प्रभावी कानून बनाए जाने की चर्चा तेज हुई थी। यह सुखद ही है कि तेलंगाना सरकार ने सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यह पहल की। सरकार का कथन है कि समाज में नैतिक दायित्वों को बढ़ावा देना इस विधेयक का मकसद है। यदि बच्चे अपना दायित्व नहीं निभाते तो कानून के जरिये उन्हें इसके लिये बाध्य किया जा सकेगा। इस विधेयक में प्रावधान है कि बच्चों द्वारा मां-बाप का भरण-पोषण न करने पर वे जिला कलेक्टर के सामने आवेदन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि यह कानून न केवल सरकारी कर्मचारियों पर बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मियों, सांसदों, विधायकों, मनीसेन सदस्यों तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भी लागू होगा। निश्चित रूप से भारतीय परिवार परंपरा में सदियों से गरिमापूर्ण स्थान रखने वाले माता-पिता के सम्मान व जीवन-यापन सुनिश्चित करने की दिशा में यह विधेयक एक मील का पत्थर स्थापित हो सकता है। इस विधेयक में जहां कलेक्टर को नामित प्राधिकारी बनाया गया है, वहीं माता-पिता को भी संपत्ति के बंटवारे की स्थिति व आय की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। ऐसे मामलों में माता-पिता तथा कर्मचारी को सुनवाई का मौका मिलेगा। कलेक्टर को साठ दिनों के भीतर शिकायत का निस्तारण करना होगा। सैधले के बाद कर्मचारी के वेतन से काटी गई राशि मां-बाप के खाते में जाएगी। उल्लेखनीय है कि केवल जैविक माता-पिता ही नहीं, सौतेले माता-पिता भी शिकायत करने के हकदार होंगे। इस विधेयक में इस बात का प्रावधान भी है कि इस बाबत शिकायतों की सुनवाई के लिये वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया जाएगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आयोग के मुख्य आयुक्त के रूप में काम करेंगे। अर्ध न्यायिक शक्तियों वाले आयोग में प्रशासन व सामाजिक क्षेत्र के अनुभवं वाले दो सदस्य भी होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह विधेयक वरिष्ठ नागरिकों के जीवन-यापन व सम्मान बहाली में सहायक होगा।

मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने और कूटनीति को विफल बताने वालों को यह रिपोर्ट देखनी चाहिए

“

देखा जाये तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को झकझोर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से भारत पहले अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग चालीस से पैंतालीस प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है उस पर दबाव बढ़ने से कई तरह की अटकलें लगाई गईं।

प्रेरणा

स्वाधीनता का मूल्य: तलवार की पुकार और जागता हुआ रोम

मानव इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति उसके खजाने, महलों या बाहरी वैभव में नहीं होती, बल्कि उसके नागरिकों के साहस, आत्मसम्मान और एकता में होती है। जब कोई समाज अपने स्वाभिमान को धन से ऊपर रखता है, तभी वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र कहलाने योग्य बनता है। प्राचीन रोम की यह घटना उसी अमर सत्य का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक समय था जब रोम अपनी समृद्धि, संगठन और सैन्य शक्ति के कारण विश्व में प्रसिद्ध था। लेकिन हर महान शक्ति को तरह रोम को भी एक दिन ऐसी परीक्षा का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। एक शक्तिशाली शत्रु ने अचानक रोम पर आक्रमण कर दिया। दुश्मन की सेना इतनी विशाल और संगठित थी कि उसने शहर को चारों दिशाओं से घेर लिया। शहर के द्वार बंद हो गए, रातें अवरूढ़ हो गए और लोगों के मन में भय की लहर दौड़ गई। चारों ओर असुरक्षा और चिंता का वातावरण फैल गया। आम नागरिक अपने परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। बाजारों में सन्नाह छा गया और गलियों में बेवनेरी फैल गई। हर कोई यही सोच रहा था कि इस संकट से कैसे बचा जाए। ऐसी स्थिति में रोम के प्रमुख सभासदों और बुद्धिजीवियों की एक सभा बुलाई गई, ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। सभा में लंबे समय तक विचार-विमर्श हुआ। कुछ लोगों का मत था कि दुश्मन से सीधा युद्ध करना अत्यंत जोखिम भरा होगा, क्योंकि उसकी सेना संख्या और संसाधनों में अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने वाले और मोदी की विदेश नीति को विफल बताने वाले विपक्षी नेताओं को यह देखना चाहिए कि जब भारत के सामने ऊर्जा संकट मंडराया तो दुनिया के वही देश मदद के लिए खड़े हो गए जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों तक भरोसे का रिश्ता बनाया था। खासकर अफ्रीकी देशों से बढ़ते आयात ने यह साबित कर दिया है कि भारत ने समय रहते अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाया था। आज वही रिश्ते और रणनीतिक फैसले भारत की ढाल बनकर खड़े हैं और यही असली कूटनीति की ताकत है।देखा जाये तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को झकझोर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से भारत पहले अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग चालीस से पैंतालीस प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है उस पर दबाव बढ़ने से कई तरह की अटकलें लगाई गईं। लेकिन भारत न तो घबराया और न ही संकट में फंसा। इसका कारण है मोदी सरकार की दूरदर्शी ऊर्जा नीति और समय रहते उठाए गए रणनीतिक कदम। आज स्थिति यह है कि भारत में कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी की उपलब्धता एक महीने पहले की तुलना में काफी बेहतर हो चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी प्रकार की ऊर्जा की कमी नहीं है और पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारु बनी हुई है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित रणनीति का परिणाम है। देखा जाये तो सबसे बड़ा बदलाव आया है ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण में। एक दशक पहले तक भारत केवल 27 देशों से कच्चा तेल लेता था, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 41 हो चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि



भारत अब किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। अमेरिका, रूस, कनाडा, नार्वे से लेकर अफ्रीकी देशों जैसे नाइजीरिया, अल्जीरिया और अंगोला तक भारत ने अपने ऊर्जा संबंधों को विस्तार किया है। एलएनजी के लिए कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और मोजाम्बिक जैसे नए साझेदार जुड़े हैं। यही नहीं, रणनीतिक भंडारण की दिशा में भी भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पिछले 11 वर्षों में 5.3 मिलियन टन का रणनीतिक तेल भंडार तैयार किया गया है और अतिरिक्त क्षमता पर तेजी से काम चल रहा है। इसका

मतलब यह है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत के पास आपूर्ति बनाए रखने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है।

मोदी सरकार ने केवल आपूर्ति बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि प्रबंधन को भी मजबूत किया। चौबीसों घंटे निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया और एक अंतर मंत्रालयी समूह रोज बैठक कर हालात का आकलन कर रहा है। जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए और राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।

यहां सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कूटनीतिक सक्रियता। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान और अमेरिका जैसे देशों के नेताओं से लगातार संपर्क बनाए रखा। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हुई और आपूर्ति बाधित नहीं हुई। यह वही देश हैं जिनसे भारत ने संकट के समय पहले भी सहयोग किया था और आज वही रिश्ते काम आए। सामरिक दृष्टि से देखें तो यह पूरी स्थिति भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति की बड़ी परीक्षा थी। पश्चिम एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्र में तनाव

नक्सलवाद मुक्त भारत की डेडलाइन पूरी, खाब अधूरी, अब अर्बन नक्सलियों पर नजर!

देश के 'पीएम इन चेंजिंग' और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों और आतंकवादियों की कमर तोड़ने में अभूतपूर्व और उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि भारत अभी पूरी तरह नक्सलवाद और आतंकवाद मुक्त हुआ है। हां, सरकार की कोशिशें सराहनीय हैं। यदि शाह अपने नेक मकसद में कामयाब हुए तो प्रधानमंत्री पद की उनकी दावेदारी और पुख्ता हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मनमाफिक राष्ट्रीय टीम पहले से ही बना रखी है। यह ठीक है कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था, और आतंकवाद समाप्ति को लेकर ऐसा कोई दुरुह लक्ष्य घोषित नहीं किया गया था और कड़ी कार्रवाई गतिमान है, लेकिन पूरे देश की बात छोड़ दी जाए तो खुद दिल्ली-एनसीआर से ब्रेक के बाद सामने आने वाले मामले इस बात की चुगली कर रहे हैं कि उद्देश्यपूर्ति काफ़ी जटिल है।

ऐसा इसलिए कि नक्सलियों और आतंकवादियों को बौद्धिक और आर्थिक खुराक देने वाली जमात राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक हलकों में सक्रिय हैं। प्रशासनिक गलियोंार तक में इनकी जातिवादी और सांप्रदायिक पैठ है।जबतक इनकी शिनाख्त और गिरफ्तारी नहीं होती, उद्देश्य अधूरा रहेगा। संभव हो कुछ तत्व सत्ताधारी दल से भी डायरेक्ट या भाया मीडिया सम्बन्धित हों। आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में नक्सली गतिविधियाँ बनी हुईं हैं। फरवरी 2026 तक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 6-7 रह गई थी, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र (बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर) में। वहीं, मार्च 2026 के अंत में सुकमा में नक्सली मुठभेड़ हुईं, जहाँ एक नक्सली मारा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि नक्सलवाद लगभग समाप्ति की कगार पर है, लेकिन औपचारिक घोषणा प्रक्रिया पूरी होने पर होगी। सरकारी दावा करते हुए अमित शाह ने 30 मार्च 2026 को लोकसभा में कहा कि "देश नक्सल मुक्त हो चुका है" और "नक्सलवाद विवृत्ति की ओर है।" 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के ठीक पहले ही ऑपरेशन चल रहे थे, जिसमें सैकड़ों नक्सली मारे गए थे। आत्मसमर्पण कर चुके हैं। फिर भी, बस्तर में ऑपरेशन तेज कर दिए हैं, जैसे कुर्गुडालू पहाड़ मॉडल पर आधारित लंबे अभियान। नक्सलियों के सहयोगी नेटवर्क (एड नेटवर्क) को निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही 567 मजबूत पुलिस स्टेशन और 336 नए सैन्य स्थापित किए गए। मुठभेड़ों और घेराबंदी से नक्सली कमांडरों को खत्म करने पर फोकस है। वहीं नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास पर बल दिया गया है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए उदार नीति लागू है, जिसमें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और रोजगार दिया प्रभावित जिले 126 (2010) से घटकर 6-7 (2026) पर पहुंच गए और ज्यादातर नक्सली मारे गए। 700+ तो हाल के वर्षों में।वहीं, आत्मसमर्पण करने वाले 4,800+ नक्सली दूसरे धंधों में जुड़ चुके हैं। बहरहाल, नक्सलवाद बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन पूर्ण मुक्ति की घोषणा अभी बाकी है। भारत में नक्सल प्रभावित 6

अभियान

यमुनोत्री धाम: भक्ति, तप और आत्मशुद्धि से मोक्ष की ओर अग्रसर पहला पावन द्वार

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में तीर्थयात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की गहराईतक उतरने वाली एक दिव्य साधना मानी जाती है। यह वह मार्ग है, जहां मनुष्य अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानने का प्रयास करता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। अनादिकाल से चार धाम यात्रा को इसी आध्यात्मिक यात्रा का सर्वोच्च रूप माना गया है, जिसमें यमुनोत्री धाम का स्थान प्रथम और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल यात्रा का आरंभिक बिंदु नहीं, बल्कि भक्ति, संयम और आत्मशुद्धि की पहली सीढ़ी है, जो मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

प्राचीन काल में चार धाम यात्रा को जीवन के अंतिम चरण, अर्थात् वानप्रस्थ या संन्यास के समय किया जाने वाला पवित्र अनुष्ठान माना जाता था, जब व्यक्ति सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता था, तब वह इस यात्रा पर निकलकर अपने जीवन को आध्यात्मिक पूर्णता प्रदान करता था। किंतु समय के साथ यह धारणा बदल गई है। आज यह यात्रा केवल युद्धों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर आयु वर्ग के लोग इसमें भाग लेकर अपने जीवन में आध्यात्मिक संतुलन और शांति स्थापित

करने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं, बेहतर सड़कों और व्यवस्थाओं के कारण यह यात्रा अब पहले की तुलना में अधिक संख्या में हो गई है, जिससे श्रद्धालुओं को मुश्किल में निरंतर वृद्धि हो रही है। उत्तराखंड की पवित्र भूमि, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, अपने भीतर असंख्य आध्यात्मिक रहस्यों और दिव्य शक्तियों को समेटे हुए है। इसी भूमि में स्थित यमुनोत्री धाम चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यह उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील में समुद्र तल से लगभग दस हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय की ऊंची-ऊंची चोटियां, बर्फ से ढके पर्वत, स्वच्छ जलधाराएं और शीतल वातावरण इस स्थान को अद्वितीय बनाते हैं। यहां पहुंचकर ऐसा प्रतीत होता है मानो मनुष्य सांसारिक कोलाहल से दूर किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर रहा हो, जहां केवल शांति, पवित्रता और ईश्वर का सान्निध्य अनुभव होता है। यमुनोत्री धाम का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा और व्यापक है। यह वह स्थान है, जहां यमुना नदी का पृथ्वी पर अवतरण माना जाता है। यद्यपि यमुना का वास्तविक उद्गम कालिंद ग्लेशियर और एक बर्फीली झील है, जो मंदिर से कुछ किलोमीटर ऊपर स्थित है, फिर भी मंदिर परिसर को ही

मुख्य तीर्थ स्थल माना जाता है। यहां यमुना जी की पूजा दो रूपों में की जाती है—एक प्राकृतिक नदी के रूप में और दूसरा मंदिर में स्थापित देवी के विग्रह के रूप में। यह द्वैत रूप हमें यह सिखाता है कि प्रकृति और ईश्वर एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनों का सम्मान करना आवश्यक है। धार्मिक ग्रंथों में यमुना को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। वे भगवान के रूप की पुत्री और यमराज की बहन हैं, जिससे उनका संबंध जीवन और मृत्यु दोनों से जुड़ा हुआ है। यह संबंध एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। यमुना का वाहन कछुआ माना जाता है, जो संयम, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। यह प्रतीक हमें यह सिखाता है कि आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य और आत्मसंयम अनिवार्य हैं। यमुनोत्री धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, कूर्म पुराण और अन्य अनेक प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार यह स्थान त्र्यंभु-मृगियों की तपस्थली रहा है, जहां उन्होंने कठोर साधना करके आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त

कीं। महर्षि असित का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने इस स्थान को खोजकर यहां अपना आश्रम स्थापित किया और अपना सम्पूर्ण जीवन तपस्या में व्यतीत किया। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन गंगा और यमुना दोनों नदियों में स्नान करते थे, लेकिन वृद्धावस्था में जब उनके लिए यह संभव नहीं रहा, तब दोनों नदियां स्वयं उनके आश्रम के समीप प्रकट हुईं। यह कथा इस स्थान की दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है। यमुनोत्री क्षेत्र में अनेक पवित्र कुंड भी स्थित हैं, जिनमें सूर्यकुंड विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह एक गर्म जल का स्रोत है, जहां श्रद्धालु चालव या आलू को कपड़े में बांधकर पकाते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह अनुभव अत्यंत अद्भुत होता है, क्योंकि हिमालय की टंडी जलवायु के बीच यह गर्म जल स्रोत प्रकृति के एक चमत्कार के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा, यहां स्थित सप्तकुंड और गोरख दिव्या सेरोवर भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें प्राचीन काल की तपस्याओं का प्रतीक माना जाता है। चार धाम यात्रा का आध्यात्मिक महत्व केवल तीर्थ स्थलों के दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक क्रमबद्ध साधना

का मार्ग है। यमुनोत्री से यात्रा की शुरूआत होती है, जहां भक्ति का बीज बोया जाता है। इसके बाद गंगोत्री में जान की प्राप्ति होती है, केदारनाथ में वैराग्य की अनुभूति होती है और अंत में बदरीनाथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह यात्रा जीवन के चार प्रमुख आध्यात्मिक चरणों में अत्यंत शुरु माना जाता है और इसे नए कार्यों के आरंभ के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। कपाट खुलने के साथ ही हजारों श्रद्धालु इस पवित्र धाम की ओर प्रस्थान करते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं। आधुनिक युग में, जहां जीवन की गति अत्यंत तीव्र हो गई है और मनुष्य निरंतर तनाव और चिंताओं से घिरा रहता है, ऐसे में यमुनोत्री धाम जैसी पवित्र स्थली एक शरणस्थली का रूप में उभरती है। यह स्थान केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक

संतुलन प्राप्त करने का माध्यम भी है। यहां आकर मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने विचारों को शुद्ध करता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का प्रयास करता है। यमुनोत्री धाम हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर निहित है। जब हम भक्ति, श्रद्धा और संयम के साथ जीवन जीते हैं, तो हम उस परम सत्य के करीब पहुंचते हैं, जिसे मोक्ष कहा जाता है। यह धाम हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का गहरा संबंध है, और दोनों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अंततः, यमुनोत्री केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरूआत है, जो मनुष्य को आत्मशुद्धि, भक्ति और मोक्ष की ओर ले जाती है। यह वह स्थान है, जहां से जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज प्रारंभ होती है और जहां हर श्रद्धालु अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नई चेतना और एक नई दिशा प्राप्त करता है। यही इस पावन धाम की सबसे बड़ी विशेषता है, जो इसे सदियों से आस्था का केंद्र बनाए हुए है और आगे भी इसे उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजनीय बनाए रखेगी।

भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को मिला नया सामर्थ्य : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से साणंद में 3300 करोड़ रुपए के 'केन्स सेमीकॉन' ओएसएटी प्लांट का शुभारंभ

▶▶ ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभरा साणंद, 'केन्स सेमीकॉन' ओएसएटी प्लांट की दैनिक 63 लाख चिप उत्पादन क्षमता
▶▶ टेक फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट : प्रधानमंत्री के करकमलों से गुजरात में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के नए युग का प्रारंभ
▶▶ देश को ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की 'ड्राइविंग सीट' तक पहुंचाने में गुजरात अग्रसर

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद जिले के साणंद से केन्स सेमीकंडक्टर ओएसएटी फैसिलिटी का शुभारंभ कराते हुए कहा कि यह 'डिकेड' यानी दशक भारत का 'डेकेड' है। उन्होंने कहा कि आज भारत ने तकनीकी क्षेत्र में जो नई पहलें की हैं, वे आगामी दशकों में वैश्विक स्तर पर देश के नेतृत्व को और मजबूत बनाएंगे। वैश्विक बाजार में भारत के आज एक विश्वसनीय सेमीकंडक्टर सप्लायर के रूप में उभर रहे होने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने जोड़ा कि साणंद में तैयार हुई चिप्स अमेरिका पहुंच कर समग्र विश्व को प्रकाशित करेगी। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत का वर्तमान वैश्विक मार्केट 4.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसे वर्ष 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का यह कालखंड केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा का समय नहीं है, बल्कि भविष्य के टेक लैंडस्केप को आकार देने का समय है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2021 में भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का प्रारंभ किया गया था। यह केवल एक औद्योगिक नीति नहीं है, अपितु वैश्विक स्तर पर भारत के आत्मविश्वास की उद्घोषणा है। उन्होंने जोड़ा कि आज का नया भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं है, बल्कि इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोडवाडिया भी उपस्थित रहे। गुजरात की एक दिवसीय यात्रा पर पधार प्रधामंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साणंद में केन्स सेमीकॉन की अत्याधुनिक आउटसोर्सड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) फैसिलिटी का उद्घाटन कर देश के सेमीकंडक्टर मिशन को नया सामर्थ्य प्रदान किया है। साणंद जीआइडीसी में लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ यह प्लांट भारत के सेमीकंडक्टर

मिशन अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मील का पथर सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने प्लांट का लोकार्पण करने के बाद सुविधाओं का सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने केन्स के युवा इंजीनियरों के साथ संवाद कर उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया। प्रधानमंत्री के करकमलों से एक ओर प्लांट का शुभारंभ होने से गुजरात में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के नए युग का प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्स के उपाध्यक्ष श्री रमेश मोदी ने भारत का वर्तमान वैश्विक मार्केट 4.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसे वर्ष 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का यह कालखंड केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा का समय नहीं है, बल्कि भविष्य के टेक लैंडस्केप को आकार देने का समय है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2021 में भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का प्रारंभ किया गया था। यह केवल एक औद्योगिक नीति नहीं है, अपितु वैश्विक स्तर पर भारत के आत्मविश्वास की उद्घोषणा है। उन्होंने जोड़ा कि आज का नया भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं है, बल्कि इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोडवाडिया भी उपस्थित रहे। गुजरात की एक दिवसीय यात्रा पर पधार प्रधामंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साणंद में केन्स सेमीकॉन की अत्याधुनिक आउटसोर्सड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) फैसिलिटी का उद्घाटन कर देश के सेमीकंडक्टर मिशन को नया सामर्थ्य प्रदान किया है। साणंद जीआइडीसी में लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ यह प्लांट भारत के सेमीकंडक्टर

नौवें है। आज देश के छह राज्यों में 1.60 लाख करोड़ रुपए की लागत से 10 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भविष्य के आयोजन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन के प्रथम फेज की सफलता के बाद अब हमने 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' की ओर कदम बढ़ाए हैं। हमारा प्रयास अब एक 'फुल स्टेक' भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करना है। बहुत ही कम समय में देश में 85 हजार से अधिक डिजाइन प्रोफेशनल्स तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अपार संभावनाओं की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में विद्यमान असीमित संभावनाओं के कारण दुनियाभर के निवेशकों में भारत के प्रति भारी उत्साह है। हमारा लक्ष्य हमारी आवश्यकता की अधिक से अधिक चिप्स प्रदान में ही बनाने का है। क्रिटिकल मिनरल्स और उनकी सप्लाइ चैन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षित सप्लाइ चैन के लिए भारत ने 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन' शुरू किया है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरलम जैसे तटीय राज्यों को जोड़कर 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' के निर्माण की भी घोषणा की गई है। यह नेटवर्क माइनिंग, रिफाइनिंग और मैनुफैक्चरिंग की एक मजबूत चैन बनाएगा, जो भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेगी। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई/एडॉप्शन पर है। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कर देते हुए प्रोत्साहित किया है और सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता केवल एक चिप तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्वीन एनर्जी, डिफेंस तथा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की मजबूती की

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

केन्स सेमीकॉन के ओएसएटी प्लांट के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने विकास की तेज गति पकड़ी है। आज साणंद में केन्स सेमीकंडक्टर प्लांट कार्यान्वित हुआ है, यह एक अनूठा मील का पथर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने गत महीने साणंद स्थित माइक्रोन फैसिलिटी का उद्घाटन किया था और आज केन्स सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ साणंद-धोलेरा को सिलिकॉन वैली बनाने की दिशा में एक विशेष कदम सिद्ध होगा।

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव

▶▶ प्रधानमंत्री की विजनी लीडरशिप में भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में टेक ऑफ कर लिया है।
▶▶ भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वर्ष 2047 तक शीर्षस्थ तीन देशों में स्थान प्राप्त कर लेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

▶▶ यह 'डिकेड' (दशक) भारत का 'डेकेड' है।
▶▶ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत का वर्तमान वैश्विक मार्केट 4.5 लाख करोड़ रुपए का, वर्ष 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य।
▶▶ साणंद में तैयार हुई चिप्स अमेरिका पहुंच कर समग्र विश्व को प्रकाशित करेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ सेमीकंडक्टर से एआई सहित इमर्जिंग सेक्टर में गुजरात को हब बनाने के लिए 'नमो गुजरात कौशल्य तथा रोजगार मिशन' के लिए राज्य के बजट में प्रावधान।
▶▶ केन्स सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ साणंद-धोलेरा को सिलिकॉन वैली बनाने की दिशा में विशेष कदम सिद्ध होगा।
▶▶ डिजिटल तथा टेक्नोलॉजी की क्रांति में भारत अग्रणी बने, उसमें सर्वोच्च योगदान देने के लिए गुजरात सक्षम एवं समर्थ साथ राज्य में लिए सक्षम और समर्थ है। इतना ही करने के लिए 'विकसित भारत, विकसित गुजरात' के ध्येय मंत्र के साथ गुजरात आगे बढ़ रहा है।



मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केन्स प्रोजेक्ट को भारत सेमीकंडक्टर मिशन तहत 2024 में मंजूरी मिली थी, और आज यह कार्यान्वित हो रहा है, जो गुजरात की विकास की गति को साबित करता है। गुजरात के युवाओं के सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवा सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सेंटर जैसी सुविधाओं के लिए कुशल वर्कफोर्स की आवश्यकता को पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में गुजरात को हब बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में 'नमो गुजरात कौशल्य तथा रोजगार मिशन' की भी घोषणा की है। इसके साथ ही, राज्य की यूनिवर्सिटियों में भी एडवांस मटेरियल सेंटर और सेमीकंडक्टर पाठ्यक्रमों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में साणंद और धोलेरा में तैयार हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लांट एंड पैसिफिटी के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित हो रहा है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी की क्रांति में भारत को अग्रणी बनाने में गुजरात भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसरों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव

वर्ष 2026 के अंत तक कुल चार प्लांट शुरू हो जाएंगे। नवंबर 2027 में दो और सेमीकंडक्टर प्लांट तथा वर्ष 2028 में धोलेरा में फैन प्लांट भी कार्यरत हो जाएगा। इस प्रकार, देश भर में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए आवश्यक केमिकल्स, गैस और चिप बनाने की मशीनें आदि सभी का उत्पादन भारत में ही हो। उन्होंने कहा कि देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश की 315 यूनिवर्सिटियों के 60,000 युवा इंजीनियरों में सेमीकंडक्टर में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि देश के युवा 2एमएम की सेमीकंडक्टर चिप की

डिजाइन तैयार कर रहे हैं। देश में दुनिया की सबसे जटिल (कोम्प्लेक्स) चिप की डिजाइन से लेकर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है। सेमीकंडक्टर प्लांट के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रघु पणिकर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी नेतृत्व और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के स्पष्ट गाइडलाइन के अभाव में जो प्रतिभाएं विदेश पलायन कर गई थीं, वे आज सरकार की उद्योग-उन्मुख नीतियों और प्रोत्साहिक फंडिंग के कारण भारत में ही नए स्टार्टअप एवं कुशल वर्कफोर्स तैयार कर रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते

हुए कहा कि 'भारत का आगमन हो चुका है' और पूरा इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम अब 'आईएसएम 2.0' (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0) के नए युग में प्रवेश करने को तैयार है। उल्लेखनीय है कि केन्स की यह अत्याधुनिक आउटसोर्सड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) फैसिलिटी लगभग 63 लाख चिप्स की दैनिक उत्पादन क्षमता के साथ साणंद में स्थापित करेगी तथा भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्लांट के उद्घाटन के साथ गुजरात देश को ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की 'ड्राइविंग सीट' तक पहुंचाने में नेतृत्व कर रहा है। भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2024 में 'केन्स सेमीकॉन' ओएसएटी फैसिलिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। जिसका निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा कर देश और गुजरात को इंजीनियरिंग क्षमता का परिचय दिया है। यह प्लांट केवल चिप पैकजिंग और टैस्टिंग की सुविधा ही नहीं देगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं के लिए उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसरों का भी निर्माण करेगा। 'केन्स सेमीकॉन' ओएसएटी प्लांट के उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायकों, टेक्नोलॉजिकल जर्नलों को पूरा करने में सहयोग देना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव सुश्री पी. भारती, केन्स असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) फैसिलिटी का उद्घाटन कर देश के सेमीकंडक्टर मिशन को नया सामर्थ्य प्रदान किया है। साणंद जीआइडीसी में लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ यह प्लांट भारत के सेमीकंडक्टर

पश्चिम रेलवे द्वारा आधुनिक पीएससी संरचना से पुरातन,पुल का उन्नयन कर सेपटी एवं स्थायित्व में वृद्धि

पश्चिम रेलवे द्वारा कादिवली और बेरीवली स्टेशनों के बीच स्थित पुल संख्या 61 के री-गार्डरिंग कार्य के माध्यम से एक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक उन्नयन किया गया, जो सुरक्षित एवं अधिक सुदृढ़ उपनगरीय नेटवर्क के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 1897 के विक्टोरियन काल में निर्मित इस 129 वर्ष पुराने पुल को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उसकी जगह आधुनिक एवं उच्च क्षमता वाली संरचना स्थापित की गई है, जो वर्तमान परिचालन एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनोद अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापन के अनुसार, यह कार्य 28 मार्च 2026 को 22:30 बजे से 29 मार्च 2026 को 19:30 बजे तक निर्धारित मेगा ब्लॉक के दौरान किया गया। इसके अतिरिक्त, 29 मार्च 2026 को प्रातः

स्टील गर्डरों की तुलना में अधिक मजबूती, टिकाऊपन तथा भार वहन क्षमता प्रदान करते हैं, जो जंग-रोधी होते हैं, कम रखरखाव की आवश्यकता होती है तथा बेहतर संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे सभ्य उपनगरीय रेल यातायात एवं प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इसके उपयोग से समग्र सुरक्षा में वृद्धि के साथ-साथ ट्रेन परिचालन अधिक सुगम एवं प्रभावी होता है। इस उन्नयन कार्य के निष्पादन में उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों एवं अत्याधुनिक मशीनरी का उपयोग किया गया, जिसमें हेवी-ड्यूटी क्रेन, हाइड्रो मशीनें, पोकेलोन एक्सकावेटर तथा जैसीबी उपकरण शामिल थे। ट्रेक कटिंग, गर्डर

हटाना, नई संरचनाओं को उठाना एवं स्थापित करना तथा एलान्डमेंट जैसे कार्य उच्च सटीकता के साथ संपन्न किए गए। 200 से अधिक कर्मियों की समर्पित टीम ने निरंतर कार्य करते हुए उत्कृष्ट योजना, समन्वय एवं तकनीकी दक्षता का परिचय दिया। वरिष्ठ मंडल इंजीनियर श्री अजय सिंह राजपूत के अनुसार, यह पहल पश्चिम रेलवे की मानसूत तैयारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस उन्नयन का उद्देश्य भारी वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के दौरान अवसंरचना की विश्वसनीयता, स्थिरता एवं सेफ्टी को सुदृढ़ करना है। यह परिवर्तन मुंबई के लाखों दैनिक यात्रियों के लिए एक अधिक मजबूत, टिकाऊ एवं भविष्य के लिए तैयार रेलवे नेटवर्क के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के कर्मचारियों द्वारा एक बार फिर उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी का परिचय दिया गया है। दिनांक 31/03/2026 (मंगलवार) की सुबह भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर गाड़ी संख्या 59204 भावनगर-बोदाद दैनिक पैसेंजर के एक यात्री श्री प्रेमजीभाई वानिया, निवासी सोनगढ़, अपना कीमती मोबाइल फोन अनारक्षित टिकट खिड़की पर अनजाने में भूल गए। इट्यूटी पर तैनात टिकट बुकिंग क्लर्क श्री विक्रमसिंह मकवाना एवं

भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर रेलकर्मियों की ईमानदारी एवं तत्परता की सराहनीय मिसाल

श्री रणजीतसिंह चौहान ने तत्परता दिखाते हुए उक्त मोबाइल को सुरक्षित अपने पास रखा तथा तुरंत उद्घोषणा (अनाउंसमेंट) करवाकर संबंधित यात्री को बुलाया। यात्री की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात उनका मोबाइल उन्हें सकुशल वापस लौटा दिया गया।

अपने खोए हुए मोबाइल की सुरक्षित प्राप्ति पर यात्री ने रेलवे प्रशासन एवं संबंधित रेलकर्मियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह पिछले दस दिनों में दूसरा अवसर है जब श्री विक्रमसिंह मकवाना द्वारा इस प्रकार की ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने संबंधित वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में सकुशल वापस लौटा दिया गया।

श्री रणजीतसिंह चौहान ने तत्परता दिखाते हुए उक्त मोबाइल को सुरक्षित अपने पास रखा तथा तुरंत उद्घोषणा (अनाउंसमेंट) करवाकर संबंधित यात्री को बुलाया। यात्री की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात उनका मोबाइल उन्हें सकुशल वापस लौटा दिया गया।

अपने खोए हुए मोबाइल की सुरक्षित प्राप्ति पर यात्री ने रेलवे प्रशासन एवं संबंधित रेलकर्मियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह पिछले दस दिनों में दूसरा अवसर है जब श्री विक्रमसिंह मकवाना द्वारा इस प्रकार की ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने संबंधित वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में सकुशल वापस लौटा दिया गया।

पश्चिम बंगाल चुनावों में गैर-बंगाली समुदायों को जोड़ने के लिए ममता बनर्जी का रणनीतिक प्रयास

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से भवानीपुर सीट के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। बनर्जी के संदेश को राज्य के प्रभावशाली व्यापार और पेशेवर समुदायों के बीच समर्थन जुटाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान दिवस के अवसर पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राजस्थानी और मारवाड़ी समुदायों से संपर्क साधा और उन्हें 'बंगाली परिवार' का अभिन्न अंग बताते हुए राज्य के विकास में उनकी भूमिका की सराहना की। सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बनर्जी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थानी और मारवाड़ी समुदायों के योगदान ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सरकार उनकी निरंतर प्रगति के लिए 'शांति, खुशी और सद्भाव' का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए

प्रतिबद्ध है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह प्रयास शुरू किया गया है। राजनीतिक विश्लेषक इस संदेश को गैर-बंगाली भाषी समुदायों, विशेष रूप से मारवाड़ियों और राजस्थानियों को अपने साथ जोड़ने का एक रणनीतिक प्रयास मानते हैं, जिन्होंने पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। विश्लेषकों का कहना है कि दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा संदेश अधिक महत्वपूर्ण है, जहां मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा गैर-बंगाली भाषी हिंदू हैं, जिनमें गुजराती, राजस्थानी और मारवाड़ी शामिल हैं। इन समूहों को अक्सर भाजपा का प्रमुख समर्थक आधार माना जाता है। भवानीपुर, जहां बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। उन्हें विपक्ष के नेता सुचेन्द्र अधिकारी से कड़ी चुनौती मिल रही है, जो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा असारवा — खेड़ब्रह्मा के बीच रोज़ाना मेमू सेवा शुरू की जाएगी

| ट्रेन क्र. | प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य | लागू होने की तारीख | प्रस्थान | आगमन |
|------------|---------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 69251 | असारवा - खेड़ब्रह्मा | 01.04.2026 | 18:25 बजे | 21:10 बजे (उसी दिन) |
| 69252 | खेड़ब्रह्मा - असारवा | 02.04.2026 | 06:45 बजे | 09:30 बजे (उसी दिन) |

होटल: दोनों दिशाओं में सरदारग्राम, नरोडा, डभोडा, नांदोल देहेगाम, रखियाल, तलोद, प्रांतिज, सोनासन, हिम्मतनगर और इडर स्टेशन।
संरचना: सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच।

समय और उठराव के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं।

पश्चिम रेलवे हमें लाइक और फॉलो करें
wri.indianrailways.gov.in

Facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें

भावनगर रेलवे मंडल के TRD एवं TRO विभाग द्वारा मार्च माह में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

यात्रियों की सुरक्षा, विश्वसनीयता एवं सुचारु रेल संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के TRD (Traction Distribution) एवं TRO (Traction Rolling Operation) विभागों द्वारा मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में मार्च 2026 के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार TRD विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ:

एंटी-मंकी ड्रिवाइस की स्थापना: बोटाद-गांधीग्राम खंड में बंदरों के कारण बार-बार ट्रिपिंग की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इस समस्या के समाधान हेतु इस खंड में एंटी-मंकी ड्रिवाइस लगाए गए हैं, जिससे ट्रिपिंग की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है (39 से घटकर 18)।

फीडर कम्पेन्शन जॉइंट का प्रावधान: भावनगर मंडल के सभी सेक्शनों में स्पाइडर टाइप फीडर जॉइंट्स को हटाकर कम्पेन्शन जॉइंट्स स्थापित किए गए हैं,

जिससे ओवरहेड इन्वियमेंट (OHE) की प्रणाली की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है।
TRO विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ: सतकं लोको पायलटों द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम: माह के दौरान सतकं लोको पायलटों ने आपातकालीन ब्रेक का समय पर उपयोग कर संभावित दुर्घटनाओं को टाला। एक मामले में ट्रेक पर जलता हुआ पेड़ तथा अन्य दो मामलों में लेवल क्रॉसिंग से संबंधित खतरे (खुला गेट एवं रेट बैनर प्लैग) पाए गए, जिससे समय रहते बचाव किया गया।
सेक्शन वीडियो ग्राफी एवं सिग्नल व्याख्या: क्लू की बेहतर ट्रेनिंग एवं सेक्शन की जानकारी बढ़ाने हेतु सिग्नल व्याख्या सहित सेक्शन वीडियो तैयार किए गए हैं, जिससे संचालन दक्षता में सुधार हुआ है।
वयज्जीव संरक्षण में योगदान: मंडल के सतकं क्लू द्वारा समय पर आपातकालीन ब्रेक लगाने से कुल 11 कर संभावित दुर्घटनाओं को टाला। एक की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भावनगर मंडल के इन प्रयासों से न केवल रेल संचालन अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बना है, बल्कि वयज्जीव संरक्षण एवं तकनीकी उन्नयन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं।

